गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 211
दि. 02.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

“पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा—यह राष्ट्रीय संकट है, सभी राज्य सहयोग करें”

नई दिल्ली। डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरनाक और तेजी से फैलते साइबर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब देशभर में दर्ज सभी डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इस जांच में सीबीआई को पूरी तरह सहयोग दें, ताकि ठगी के इस नए और अत्यधिक संगठित नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। अदालत ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का चलन राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा खुद को पुलिस अधिकारी, सरकारी जांच एजेंसी के सदस्य या कोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना और पीड़ितों को वीडियो कॉल के माध्यम से धमकाकर पैसे वसूलना एक संगठित अपराध का नया स्वरूप है, जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाता है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसे रोकने के लिए अलग स्तर की राष्ट्रीय समन्वय वाली जांच की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठगों के इस नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ की भी आशंका है, क्योंकि कई मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें कॉल विदेशी सर्वरों से आते हैं और पैसे म्यूल खातों के जरिए तेजी से दूसरे देशों में भेज दिए जाते हैं। अदालत ने सीबीआई को स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि ज़रूरत पड़े तो इंटरपोल (Interpol) की मदद लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन गैंग्स का पीछा किया जाए। पीठ ने कहा कि साइबर अपराध की यह श्रेणी अब सामान्य अपराध नहीं, बल्कि आर्थिक अत्याचार और राष्ट्रीय स्तर का खतरा बन गई है। अदालत ने पहले 3 नवंबर को हुई सुनवाई की याद दिलाते हुए कहा कि अब तक करीब 3,000 करोड़ की ठगी डिजिटल अरेस्ट मामलों में सामने आई है। न्यायालय ने इसे “आयरन हैंड से निपटने योग्य राष्ट्रीय समस्या” बताया था। इस बार की सुनवाई में अदालत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि बैंकिंग सिस्टम को साइबर अपराधियों द्वारा ठगी में उपयोग किए जाने वाले खातों को तुरंत ट्रैक, ब्लॉक और फ्रीज करने के लिए आधुनिक तकनीक—विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

मशीन लर्निंग—का उपयोग अभी तक बड़े पैमाने पर क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि तकनीक से लड़ाई को तकनीक ही रोक सकती है और बैंकिंग व्यवस्था को इस दिशा में बहुत तेजी से काम करना होगा।

इस मामले की पृष्ठभूमि में हरियाणा के अंबाला का वह हैरान कर देने वाला केस है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति को 3 से 16 सितंबर के बीच 1.05 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया था। साइबर अपराधियों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम से जारी आदेश दिखाकर पीड़ितों को सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे भारी रकम वसूल ली। पीड़ित ने बाद में सीधे तत्कालीन सीजेआई बी.आर. गवई को चिट्ठी लिखकर पूरी घटना बताई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब यह मामला पूरे देश के साइबर अपराध तंत्र के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि सभी IT इंटरमीडियरीज़—जैसे सोशल मीडिया कंपनियाँ, कॉल/वीडियो कॉलिंग प्लेटफ़ॉर्म, क्लाउड सर्विस प्रदाता और इंटरनेट कंपनियाँ—सीबीआई को पूरा डेटा और तकनीकी सहायता दें। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जो बैंक अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर म्यूल अकाउंट्स (वे खाते जिनका उपयोग पैसे घुमाने के लिए किया जाता है) को ऑपरेट करने में साइबर अपराधियों की मदद करते हैं, उनकी भी जांच की जाए, और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई हो।

टेलिकॉम विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि एक व्यक्ति या संस्था को कई सिम कार्ड जारी न किए जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड साइबर अपराधियों के नेटवर्क की रीढ़ हैं। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने स्तर पर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएं और उन्हें सीबीआई से लिंक करें, ताकि डेटा शेयरिंग, कॉल ट्रैकिंग और डिजिटल जांच में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि डिजिटल अरेस्ट अब एक अलग-थलग पड़ने वाला मामला नहीं रहा, बल्कि यह साइबर क्राइम का राष्ट्रीय स्वरूप है। अदालत ने एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर देश में लोगों के बैंक खातों और डिजिटल जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो इस अपराध की जड़ तक पहुँचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ खड़ा होना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश न सिर्फ साइबर अपराधियों के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि देशभर के नागरिकों को भरोसा दिलाने वाला बड़ा कदम भी है कि कानून और तकनीक दोनों मिलकर डिजिटल ठगी के बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब अत्यधिक आक्रामक मोड में उतर चुके हैं।

असम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, राज्य में भी देशभर जैसा एसआईआर लागू करने की मांग तेज

नई दिल्ली। असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। गौहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मृणाल कुमार चौधरी ने निर्वाचन आयोग के 17 नवंबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आयोग ने असम के लिए केवल “विशेष पुनरीक्षण” का निर्देश दिया था। याचिका में मांग की गई है कि असम में भी पूरे देश की तरह “विशेष गहन पुनरीक्षण” यानी एसआईआर लागू किया जाए।

याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे राज्यों में जहां एसआईआर लागू है, वहीं असम को इससे बाहर रखना न केवल मनमाना कदम है बल्कि भेदभावपूर्ण भी। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक ही देश में मतदाता सूची सुधार के दो अलग-अलग मानक नहीं रखे जा सकते, और असम जैसे संवेदनशील राज्य में तो यह और भी महत्वपूर्ण है कि गहन पुनरीक्षण किया जाए।

असम से जुड़ी ऐतिहासिक रिपोर्टों को भी याचिका में आधार बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता और राज्य के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्टों हवाला देते हुए कहा गया है कि 1997 तक असम में 40 से 50 लाख अवैध आप्रवासी रह रहे थे। याचिका के अनुसार बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासियों के कारण मतदाता सूची की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है, इसलिए राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अत्यावश्यक है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि असम में भी देश के अन्य राज्यों की तरह एसआईआर लागू किया जाए और मतदाता सूची से अवैध आप्रवासियों को व्यवस्थित ढंग से हटाया जाए। मामले की सुनवाई में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और क्या चुनाव आयोग को अपने आदेश की समीक्षा करनी पड़ेगी।

पश्चिम मेदिनीपुर में हाथियों का बढ़ता कहर, पके धान के खेत रौंदे; किसानों में गहरी दहशत, वन विभाग अलर्ट पर

पश्चिम मेदिनीपुर। जिले के नरायणगढ़ ब्लॉक का बड़ा इलाका इन दिनों हाथियों के भारी उत्पात से परेशान है। सुवर्णरेखा नदी पार कर आए चार हाथियों का झुंड—जिसमें एक विशाल दंतैल भी शामिल है—रात होते ही गांव–गांव पहुंचकर पके धान के खेत रौंद रहा है। खेत बर्बाद होने से ग्रामीणों में गहरा रोष है, जबकि वन विभाग लगातार संघर्ष कर रहा है कि किसी तरह इन हाथियों को सुरक्षित ढंग से जंगल की ओर वापस भेजा जा सके।

स्थानीय जानकारी के अनुसार बेलदा रेंज के बेलटी, सीतली, नूतनडिही, बांसचाटी, धानघोरी और महुलडांगा जैसे गांव हर शाम भय के साये में ढलते हैं। पहले तो हिजली रेंज से दो हाथी पहुंचे थे, फिर केशियाड़ी दिशा से एक और शामिल हो गया। शनिवार की देर रात कुलबनी जंगल से एक दंतैल हाथी आ मिला, जिससे झुंड और आक्रामक हो गया। गांवों को चारों ओर से धान के पके खेत घेरे हुए हैं और यही हाथियों को बार–बार यहां खींच रहा है।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में धान कटाई अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कटाई पूरी हो चुकी है। भोजन की तलाश में हाथियों का रुख इन गांवों की ओर होना स्वाभाविक है। दिन में ये झुंड घने जंगलों में छिपे रहते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही खेतों में उतर आते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की हुला पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, मगर असमतल भू–भाग, घना जंगल और खेतों में मौजूद भारी फसल इसे चुनौतीपूर्ण बना रहा है। बेलदा रेंजर तौहीद अंसारी के मुताबिक विभाग इन चारों हाथियों को बिना किसी नुकसान के जंगल की ओर मोड़ने के प्रयास कर रहा है, लेकिन पके धान के बीच हाथियों को गांव छोड़ने के लिए मनाना आसान नहीं है। बार–बार हो रही फसल बर्बादी ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत प्रभावी कदम उठाए, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे और नुकसान का उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करे। गांवों में तनाव का माहौल है और लोग डर के साये में रात गुजारने को मजबूर हैं।

वायु संकट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, कहा—पराली को राजनीति का हथियार नहीं समाधान का हिस्सा बनाएं

नई दिल्ली। देश की राजधानी सहित उत्तर भारत लगातार जहरीली हवा की गिरफ्त में है और इसी गंभीर संकट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद स्पष्ट और तीखी टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि पराली को लेकर चलने वाली बहस को राजनीतिक मोड़ देना गलत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसानों को एकतरफा दोष देना उचित नहीं है और सरकारों को यह समझना चाहिए कि प्रदूषण के पीछे कई बड़े और जटिल कारण हैं, जिन पर ईमानदार कार्रवाई की जरूरत है। अदालत ने कहा कि कोविड महामारी के दिनों में भी किसानों ने पराली जलाई थी, फिर भी आसमान साफ दिखा था, हवा शुद्ध थी और प्रदूषण नियंत्रित था, इसलिए यह मान लेना कि अकेले किसान ही वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, पूरी तरह गलत और भ्रामक है।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र और राज्यों दोनों को कड़े शब्दों में यह याद दिलाया कि प्रदूषण का मुद्दा किसी पार्टी या प्रदेश की राजनीति से ऊपर है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारें सच में समाधान चाहती हैं तो उन्हें किसानों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा, विकल्प उपलब्ध कराने होंगे और उद्योगों, वाहनों, निर्माण कार्यों तथा ऊर्जा स्रोतों पर भी सख्ती से नियंत्रण करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण एक ऐसा संकट है जो सीमाओं या राजनीति की Lines नहीं देखता—इसका असर अस्पतालों में भर्ती मरीजों से लेकर स्कूल जाते बच्चों तक हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। ऐसे में इसे राजनीतिक बयानबाजी का साधन बनाना जनता के साथ अन्याय होगा।

अदालत के सवालों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से बताया गया कि उन्होंने राज्यों, पर्यावरण एजेंसियों और संबंधित विभागों से सुझाव मंगाए हैं और इन आधारों पर एक समग्र रणनीति तैयार की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तत्काल लागू किए जाने वाले कदम कौन से होंगे, क्योंकि हालात हर साल बिगड़ते जा रहे हैं और केवल बैठकों और रिपोर्टों से हवा साफ नहीं होती। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जानकारी दी कि जल्द ही सभी सिफारिशों को मिलाकर एक विस्तृत ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ अदालत में दाखिल की जाएगी, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की योजनाएँ शामिल होंगी।

सीजेआई सूर्यकांत ने अंत में कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजने का है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब किसान, उद्योग, सरकारें और पर्यावरण एजेंसियाँ एक-दूसरे को दोष देने के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है, जिसमें केंद्र और आयोग द्वारा पेश की जाने वाली विस्तृत योजना के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी।

महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल: स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में आज मतदान, राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली बड़ी परीक्षा

मुंबई की सियासत इस दिसंबर की सुबह जैसे एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में लंबे समय से टलते आ रहे स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण आज आयोजित हो रहा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक ‘सत्ता का सेमीफाइनल’ कह रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद यह पहली बड़ी वोटिंग है, जो न सिर्फ जनता के मूड का अगला संकेत देगी, बल्कि आने वाले महीनों में होने वाले निगम, जिला परिषद और पंचायत समितियों के विशाल चुनावी दौर की भी दिशा तय करेगी।

राज्यभर के 13,355 मतदान केंद्रों पर आज 1.07 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही कई जिलों में मतदान केंद्रों पर कतारें नजर आईं—ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक उत्साह और शहरों में धीमी लेकिन steady शुरुआत। चुनाव आयोग ने 62,108 अधिकारियों-कर्मचारियों को तैनात किया है, जो इस विशाल प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराने में जुटे हैं।

इस पहले चरण में 6,705 सदस्य पदों और 264 अध्यक्ष पदों का भविष्य तय होने जा रहा है। चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैं, जिसके लिए 17,367 कंट्रोल यूनिट और 34,734 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। हालांकि 24 निकायों में नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं, अपीलों में देरी और चुनाव चिह्न आवंटन में गड़बड़ियों के चलते इनका चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिया गया है। इससे चुनावी क्षेत्रों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि कई उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए तीन दिन तक नहीं मिले—इसे आयोग ने खुद नियमों का उल्लंघन माना।

इन स्थानीय चुनावों का सबसे दिलचस्प पहलू है सत्ता और विपक्ष की सीधी, तीखी और व्यापक भिड़ंत। भाजपा, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का महा-युति गठबंधन एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस का महा विकास आघाड़ी (एमवीए) है। विधानसभा चुनावों में महायुति को मिली रिकॉर्ड जीत के बाद निगाहें इस पर हैं कि क्या वही लहर छोटी सरकारों में भी दिखेगी, या फिर सत्ता के विरुद्ध स्थानीय असंतोष विपक्ष को मजबूती प्रदान करेगा।

इसी बीच भाजपा ने मतदान से पहले ही 100 सदस्य और 3 अध्यक्ष पद निर्विरोध जीतने का बड़ा दावा किया है। इसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने मोदी और फडणवीस के नेतृत्व में जनता के विश्वास का परिणाम बताया। इससे भाजपा का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है और विपक्ष के भीतर बेचैनी।

स्थानीय निकायों पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूरे प्रदेश में 53 जनसभाएं और 2 रोड शो कर ताबड़तोड़ प्रचार किया, भीड़ से सीधे संवाद साधते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान घोषित किया। सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने भी 8 जिलों में 22 जनसभाएं और कई रोड शो कर पार्टी के लिए मजबूत माहौल बनाया। दूसरी ओर, एमवीए ने भी ताकत झोंक दी—उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने रैलियों में महायुति पर सरकार-विरोधी माहौल का दावा किया, जबकि कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ का भरोसा जताया।

चुनाव प्रचार सोमवार रात 10 बजे बंद हो चुका है। आज किसी भी तरह का विज्ञापन प्रतिबंधित है। आयोग ने मीडिया रेगुलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट सर्टिफिकेशन ऑर्डर 2025 लागू किया है ताकि आचार संहिता पूरी तरह प्रभावी रहे। डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए डबल-स्टार सिस्टम और उम्मीदवारों की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप पहली बार व्यापक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 निकायों का चुनाव रोके जाने को “गलत और उम्मीदवारों के साथ अन्याय” बताया है, हालांकि उन्होंने आयोग की स्वतंत्रता को स्वीकार भी किया। उनके इस बयान ने चुनावी बहस को और तीखा कर दिया है।

इन निकायों के बाद अभी 29 नगर निगम, 32 जिला परिषदें और 336 पंचायत समितियों के चुनाव बाकी हैं—सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह पूरा चुनावी चक्र 31 जनवरी से पहले पूरा होना है। इसलिए 2 दिसंबर की वोटिंग सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य का शुरुआती संकेत है।

यदि महायुति मजबूत प्रदर्शन करती है, तो विधानसभा की जीत का असर निकायों में भी साफ दिखाई देगा और सरकार की स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन यदि एमवीए अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, तो यह 2025-26 की पूरी चुनावी राजनीति का समीकरण बदल सकता है।

आज की वोटिंग सिर्फ छोटा चुनाव नहीं—यह महाराष्ट्र की राजनीति का असली सेमीफाइनल है, जिसका फाइनल आगामी महीनों में होना बाकी है।

संपादकीय

सहज कर्म-पथ का आह्वान है भगवद्गीता, अस्तित्व का अर्थ और मूल्य ही गीता का प्रतिपाद्य है

कालजयी श्रीमद्भगवद्गीता उस महाभारत का अंश है, जिसे भारतीय चिंतन परंपरा में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महाभारत की महागाथा में धर्म की अवधारणा ही प्रमुख है। गीता का आरंभ भी धर्म शब्द के साथ होता है। धर्म का तत्व देश, काल और पात्र के सापेक्ष होता है और गतिशील जीवन-पद्धति को इंगित करता है। ईश्वर का अवतार धर्म को पहचानने और स्थापित करने के लिए होता है। धर्म को रीति और नीति से भिन्न समझना होगा। अपने से दुर्बल की सहायता करना ही परम धर्म है। इस दृष्टि से सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष ही धर्म की समझ भी आकार लेती है। ऋग्वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र आदि सब का संज्ञान लेते हुए महाभारत रचा गया। भगवद्गीता महाभारत का हृदय सरीखा है।

भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है, पर उसके पहले वन पर्व में व्याध-गीता का भी एक आख्यान आता है। आश्चर्य यह कि दोनों हिंसा की पृष्ठभूमि में हैं। एक कसाई के घर में तो दूसरा युद्धभूमि में। भौतिक (प्रकृति) और मानसिक चैतन्य (पुरुष) का भेद दोनों में ही दिखता है। प्रकृति का सत्य विविधताओं से भरा हुआ है। मनुष्य की कल्पनाशीलता उसे चर अचर अन्य सभी जीवों या पदार्थों से अलग करती है। मनुष्य से यह अपेक्षा है कि वह पाशविक वृत्ति से ऊपर उठ कर ऊर्ध्वमुखी हो। यही जीवन में व्याप्त हीनता और क्षुधा को दूर करने वाला है।

गीता की विचारधारा सदियों से देश-विदेश में मानवीय चिंतन को प्रभावित करती आ रही है। अब तक विश्व की विभिन्न भाषाओं में गीता के तीन हजार से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। कहा जाता है कि तमाम शास्त्रों को विस्तार में पढ़ने की जगह गीता को हृदयंगम करना ही पर्याप्त है। इसमें कृष्ण स्रोत हैं और संजय सूचना या संदेश के प्रस्तोता हैं। शायद धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण के वचनों को सुनते हैं, परंतु अपने-अपने ढंग से और कदाचित भिन्न भिन्न रूपों में। अर्जुन श्रीकृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र चुप रहते हैं। वे डरे सहमे हुए हैं। वे शायद मन ही मन कृष्ण के वचनों को सुनकर गुनते-आंकते हैं।

गीता में श्रीकृष्ण विश्लेषण (सांख्य) और संश्लेषण (योग) दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने व्यावहारिक कर्म-योग, भावनात्मक भक्ति-योग और बौद्धिक ज्ञान-योग का प्रतिपादन किया है। गीता के पांचवें अध्याय में श्रीकृष्ण शरीर को नौ द्वारों वाली एक पुरी बताते हैं। गीता द्वारा मानस का विस्तार और यथार्थ का बोध संभव होता है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि आप वर्तमान परिस्थिति को तो नहीं नियंत्रित कर सकते, किंतु उस परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करें, यह जरूर चुन सकते हैं। गीता का कर्मवाद यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माता भी है। इसका संदेश यही है कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे बस में मात्र यही है कि हम परिस्थिति के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने को कहते हैं न कि फल पर।

कर्म का परिणाम भी पांच पहलुओं पर निर्भर करता है– शरीर, मन, उपकरण, विधि तथा दैव (भाग्य)। मूर्ख ही खुद को अकेले कारण मानता है। यदि हम खुद को कर्मों के परिणामों से नहीं बांधते तो कर्म भी हमको नहीं बांधते। सुख, शक्ति और स्वर्ग की कामना से किया गया कर्म जब किया जाता है तो आंख फल पर टिकी होती है न कि कर्म पर। कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच के अंतर को समझना कठिन है। बुद्धिमान लोग कर्म फल से बिना जुड़े निर्लिप्त होकर काम करते हैं। कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होने और फलेच्छा का त्याग करने पर कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त होकर कर्म करना श्रेष्ठ कर्मयोगी बनाता है। सक्रिय होना कर्म है, पर परिणाम को बिना नियंत्रित करने की चेष्टा के कर्म करना कर्म-योग है।

बस्तर में हो रहा है सुनहरा सवेरा...

> हिंसा का खेल खेलने वाले नक्सली चौतरफा सरकारी प्रयासों के चलते या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या कार्रवाई में ढेर हो रहे हैं। दूसरी ओर, जिन अंदरूनी इलाकों तक दशकों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी, वहां आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वास्तविक रूप ले रही हैं।

जब किसी भी समस्या के समाधान के प्रति नेतृत्व की इच्छा शक्ति सच्चे अर्थों में सक्रिय होती है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। नक्सलवाद के संदर्भ में जो परिणाम आज देश देख रहा है, वह केन्द्र और राज्य सरकारों के संकल्पित प्रयासों का ही फल है। जो बस्तर कभी लाल आतंक का प्रमुख गढ़ माना जाता था, वहां अब स्थायी शांति अपना आधार मज़बूत कर रही है। हिंसा का खेल खेलने वाले नक्सली चौतरफा सरकारी प्रयासों के चलते या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या कार्रवाई में ढेर हो रहे हैं। दूसरी ओर, जिन अंदरूनी इलाकों तक दशकों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी, वहां आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वास्तविक रूप ले रही हैं। पिछली उदासीन सरकारों और स्वार्थी माओवादियों ने जिन आदिवासियों को छला और लोकतंत्र से दूर रखा, वही समुदाय आज विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहा है।

भले ही नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा हो, लेकिन इसके दशकों पुराने घाव बेहद गहरे हैं। सैकड़ों जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या, विकास से पूरी पीढ़ियों को वंचित रखना और भय का वातावरण ये सब नक्सलवाद की भयावह विरासत रही है। 2000 के दशक की शुरुआत में इसकी ताकत चरम पर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे देश की "सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती" बताया, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों और संकल्प के अभाव में कांग्रेस सरकारें इस खतरे पर निर्णायक प्रहार नहीं कर सकीं।

उस दौर में बस्तर से लेकर राजनांदगांव, गरियाबंद और कवर्धा तक आतंक की जड़ें फैल चुकी थीं। नक्सलियों का लक्ष्य दंतेवाड़ा

से दिल्ली तक लाल झंडा फहराने का था, जिसे अर्बन नक्सल नेटवर्क से भी समर्थन मिलता था। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इस गंभीर खतरे को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 जिले माओवादी आतंक की चपेट में आ गए और विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इसके विपरीत, आज मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से समझा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को उनके हाल पर छोड़कर देश पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकता। मजबूत इच्छा शक्ति और कठोर कार्रवाई के परिणाम आज सामने हैं। आज बस्तर ही नहीं पूरा दंडाकारण्य क्षेत्र विकास का नया अध्याय लिखने को आतुर है। यह क्षेत्र भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा है, बस्तर में रामपाल गांव, रामाराम मंदिर (सुकमा), राकसहाड़ा और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी भगवान राम से संबंधित हैं। नक्सलवाद के खग्रास ग्रहण से अब बस्तर मुक्त हो रहा है। अब एक बार फिर यहां भगवान राम का गौरव स्थापित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय सरकार यहां राम राज्य स्थापित के लिए संकल्पित है। यही फर्क है एक तरफ इच्छा शक्ति वाली सरकार और दूसरी तरफ उदासीन शासन की नाकामी।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विपक्ष भी इस सफलता को नकारात्मक चश्मे से देखने में लगा है। कुछ नेता यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर में उद्योगपतियों के लिए जमीन तैयार करने हेतु नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है। इससे भी अधिक खतरनाक यह है कि कुछ राजनीतिक बयानबाजी नक्सलियों को आदिवासियों का संरक्षक और जंगलों का रक्षक बताने लगती है। यह सीधे-सीधे एक क्रूर, हिंसक विचारधारा को जीवित रखने की कोशिश है जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए दुर्दांत नक्सली कमांडर हिड़मा को लेकर कुछ लोग उसके हमदर्द के रूप में सामने आए हैं। कुछ तो उसे बस्तर का रक्षक तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक चाल से सावधान रहने की आवश्यकता है। हिड़मा कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं था; उसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से सने हुए थे। ऐसे हिंसक व्यक्ति को आदर्श या प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना, उसे महिमामंडित करना— नक्सलवाद को पोषित करने जैसा ही है। यह दुर्दांत हत्यारा बस्तर का आदर्श कैसे हो सकता है?

हद तो तब होती है जब दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कांग्रेसी नेता हिड़मा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए अविभाजित मध्यप्रदेश में बस्तर को "कालापानी की सजा" कहा जाता था, उस दौरान ही नक्सलियों ने यहां अपनी जड़ें मजबूत कीं। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही वर्ष 1995 में हिड़मा सहित कई युवा सरकारी उपेक्षा के कारण लाल आतंक की राह पर चल पड़े थे ।

हमारा स्पष्ट मानना है कि भगवान बिरसा मुंडा, महान योद्धा गुंडाधुर, परलकोट के राजा गेंद सिंह और शहीद वीर नारायण सिंह ही आदिवासी समाज के वास्तविक आदर्श हैं। आदिवासी समाज हिड़मा या बसव राजू जैसे हिंसक व्यक्तियों को अपना हीरो नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी परंपरा सदियों से इन्हीं महान नायकों को पूजती आ रही है।

यदि बस्तर में नक्सलवाद के उभार के मूल कारणों को याद करें तो सबसे प्रमुख कारण था आदिवासियों का प्रशासनिक तंत्र द्वारा शोषण और लगातार उपेक्षा। तब की कांग्रेस सरकारें न केवल बस्तर बल्कि देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों के प्रति उदासीन थीं। इसी खालीपन का फायदा उठाकर आंध्रप्रदेश से आए माओवादी यहां जड़ें जमाने में सफल हुए।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार की शह पर 25 मार्च 1966 को बस्तर महराज प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या हो या पुलिस अत्याचार इन घटनाओं ने सरकार और आदिवासियों के बीच अविश्वास की गहरी खाई बना दी। इसी खाई में माओवादियों ने अपनी जड़ें गहरी कीं और दशकों तक समानांतर शासन चलाते रहे। गौरतलब है कि प्रवीरचंद भंजदेव बस्तर में आदिवासियों में बेहद लोकप्रिय थे, वे सरदार वल्लभभाई पटेल के समक्ष विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजाओं में से एक थे, इसके चलते पटेल के साथ उनके करीबी संबंध बन गए थे। भजदेव ने कुछ और रियासतों को भी विलय कराने में मदद की थी, इसलिए भी कांग्रेस में एक बड़े खेमे को वे चुभने लगे थे। पटेल के नहीं रहने के बाद उनके योगदान को कमतर करने की कोशिश आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों द्वारा हुई ये किसी से छुपी नहीं है। भंजदेव का कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेद का परिणाम था कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और पार्टी छोड़ दी थी इसके बाद कांग्रेस के साथ उनका मतभेद बढ़ता चला गया, आखिरकार पुलिस ने बेरहमी से गोलियां बरसाते हुए दरबार हाल के पास ही इस महानायक की हत्या कर दी गई । यह ऐतिहासिक भूल कांग्रेस आज भी दोहरा रही है नक्सलवाद के सफाए को लेकर भ्रम फैलाकर।

इसलिए आज आवश्यकता है कि इस नए "भ्रमवाद" से सावधान रहा जाए। नक्सलवाद के सफाए के इस निर्णायक चरण में देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, न कि झूठे भ्रम और राजनीतिक चश्मे से इस राष्ट्रीय उपलब्धि को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रेरणा

प्लास्टिकजी का शासन: सुविधा की चमक में छुपी जिंदगी की कीमत

प्लास्टिक का इतिहास पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले दिमाग में यही विचार आता है कि जिसे हमने आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कहा, उसी ने हमें असंख्य सुविधाएँ भी दी हैं। शायद इसी वजह से मन में कई बार यह भावना भी उठती है कि प्लास्टिक का आविष्कार करने वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को दुनिया ने जितना सम्मान देना चाहिए था, उतना दिया नहीं। हर घर में, हर दफ्तर में, हर दुकान में, हर सड़क के मोड़ पर, कहीं न कहीं प्लास्टिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हल्का, टिकाऊ, सुंदर, रंगीन, आकार बदलने वाला, सस्ता और हर जगह उपलब्ध—ऐसा बहुमुखी साथी शायद इंसान ने पहले कभी नहीं पाया। यही वजह है कि जिन भी चीज़ों को हल्का, चमकदार और किफायती बनाना था, उनमें प्लास्टिक ने कदम-दर-कदम अपनी जगह बना ली। फ्रिज की बोतलों से लेकर पानी की टंकियों, मोबाइल कवरों से लेकर बच्चों के खिलौनों, महंगे ब्रांडों की पैकेजिंग से लेकर रसोई की रोज़मर्रा की चीज़ों तक, प्लास्टिक एक छुपा हुआ लेकिन प्रभावी नायक बनकर हमारे जीवन में फैल गया।

किसी जमाने में हमारी दादी-नानी मिट्टी, लकड़ी, धातु और काँच के बर्तनों की दुनिया में जीती थीं; आज रसोई के रैक में प्लास्टिक के दर्जनों रंग उनके चयन और आधुनिकता का परिचय देते हैं। पालीहाउस में पकती सब्जियाँ, फ्रिज में ठंडे पानी की बोतलें, बच्चों के स्कूल बैग में रखे लंच बॉक्स, दफ्तरों में बैठकर पी जाने वाली चाय तक—सबमें प्लास्टिक की मौजूदगी एक निश्चित सहजता बन गई है। यही वजह है कि कई लोगों को प्लास्टिक इतना प्रिय लगता है कि वे उसे मज़ाक में 'प्लास्टिकजी' कहकर संबोधित कर देते हैं, मानो वह कोई भरोसेमंद परिचित हो जो हर समय साथ खड़ा रहता है।

लेकिन दुनिया में कोई भी वस्तु एकतरफा नहीं होती। जिसने सुविधा दी, उसने नुकसान भी पहुँचाया। प्रकृति ने इंसान को बुद्धि दी थी, दिल भी दिया था, पर उसी इंसान ने अपनी ज़रूरतों और लालचों के चलते धरती को सबसे अधिक हानि पहुंचाई। बड़े-बड़े देशों की राजनीति, देशों के बीच की प्रतिस्पर्धाएँ, आधुनिक विकास की दौड़, उद्योगों का फैलाव—इन सबके बीच प्लास्टिक एक ऐसा हथियार बन गया जो जितना उपयोगी था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन विडंबना यह है कि कई लोग आज भी मानते हैं कि प्लास्टिक से होने वाला नुकसान दुनिया को बाँटने वाली राजनीति, नफरत का ज़हर, बढ़ती बेरोजगारी, वर्गवाद या धर्म के नाम पर खड़ी हो रही दीवारों जितना नहीं है।

फिर भी वैज्ञानिकों ने चेताया है कि प्लास्टिक अब हमारी मिट्टी में ही नहीं, हमारे भोजन, हमारे रक्त और माँ के दूध तक में पहुँच गया है। आम सब्जियों—टमाटर, गाजर, पालक—के भीतर माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। समुद्री भोजन तो लगभग प्लास्टिक की दुनिया में जी रहा है। लेकिन लाख चेतावनियों के बावजूद हम इंसान इस सुविधा की जकड़ से निकलना नहीं चाहते। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक बन चुका है कि हर चीज़ को पैक करने, हर सामान को सुरक्षित रखने, हर उत्पाद को सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जितनी बार भी बैठकें हुईं, जितने भी प्रतिबंध आए, उसकी खपत उतनी ही तेजी से बढ़ती चली गई।

अब नई पीढ़ी तो इस जीवनशैली में पूरी तरह ढल चुकी है। पैक्ड फूड, सील्ड जूस, प्लास्टिक की बोतलों में भरा पानी, सिंथेटिक स्नैक्स—उनके बचपन का हिस्सा हैं। उन्हें मिट्टी की खुशबू, पारंपरिक बांस की टोकरियाँ, धातु के लंच बॉक्स या काँच की बोतलें पुरानी और असुविधाजनक लगती हैं। दुनिया की रफ्तार ऐसी हो चुकी है कि सुविधा ही सर्वोपरि सच बन गई है। यही कारण है कि प्लास्टिक घरों में, दुकानों में, मंदिरों में, खेतों में, समुद्रों में और यहाँ तक कि हमारी नसों में भी अपनी जगह बना चुका है।

मानवीय संबंध भी आजकल प्लास्टिक जैसे ही हो गए हैं—कभी लचीले, कभी कठोर, कभी टिकाऊ, कभी टूटने वाले। समाज की संरचना भी उसी तरह बदल रही है जैसे हम चीज़ों के लिए प्लास्टिक पर निर्भर होते चले गए। यह निर्भरता इतनी मजबूत हो चुकी है कि लोग साफ कहते हैं—"प्लास्टिक छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा जी?" और सच भी यही है कि हमें इसकी आदत इतनी हो चुकी है कि बिना प्लास्टिक के आधुनिक जीवन की कल्पना तक नहीं कर पाते।

प्लास्टिकजी की यही सर्वव्यापकता हमारी सुविधा और हमारी असुविधा, दोनों की जड़ है। मनुष्य जानता है कि यह वास्तविक खतरा है, लेकिन उसी मनुष्य ने इसे अपने जीवन में ऐसा स्थान दे दिया है कि उससे दूरी बनाना अब कठिन से भी कठिन होता जा रहा है। सुविधा का यह चमकता साम्राज्य धीरे-धीरे हमारी धरती, हमारे शरीर और हमारी सोच में ऐसे समा गया है कि चाहे हम चाहें या न चाहें, प्लास्टिकजी का शासन चलता ही रहेगा—जब तक इंसान सुविधा के मोह से बाहर निकलना नहीं सीख लेता।

लोकतंत्र की सेहत पर सवाल, बढ़ता मौन गहरी चिंता पैदा करता है

दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन राजधानी में राजनीतिक पारा चढ़ने वाला है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से शुरू होने वाला यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। यानी संसद करीब 15 दिन ही चलेगी। यह सूचना भले ही प्रशासनिक कागजों में दर्ज हो, पर उसके भीतर देश की राजनीति की एक गहरी बेचैनी छिपी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब संसद के सत्र छोटे होने लगते हैं तो यह कुछ और नहीं जनता की आवाज का सिकुड़ना ही है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहां पांच सौ से अधिक लोकसभा सदस्य और ढाई सौ के करीब राज्यसभा सदस्य जनता की आवाज लेकर सदन में पहुंचते हैं, वहां सवाल यह है कि क्या इन सात सौ अस्सी से अधिक प्रतिनिधियों को मात्र पंद्रह दिनों में अपनी बात कहने का अवसर मिल पाएगा? यह गणित जितना सरल दिखता है, उतना ही खतरनाक है। अगर हर सांसद को अपने क्षेत्र की ओर से सिर्फ पांच मिनट बोलने का ही अवसर मिले, तो पैंसठ घंटे से अधिक समय चाहिए। जबकि पूरे सत्र में मुश्किल से नब्बे घंटे की कार्यवाही होती है। उसमें प्रश्नकाल, विधेयक, औपचारिक भाषण और सरकार के एजेंडे का समय जोड़ दें तो बहस के लिए क्या बचता है? शायद वही, जो लोकतंत्र के पास अब धीरे-धीरे बचा रह गया है बहुत कम समय और बहुत लंबा मौन।

संसद को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। यह वह जगह है जहां असहमति को जगह मिलती है और बहस के जरिये सच्चाई निकलती है। यहां जनता के सवालों को सत्ता के सामने रखा जाता है, पर पिछले कुछ वर्षों में यह आत्मा थका-सा लगने लगा है। संसद अब बहस का नहीं, बल्कि विधेयक पारित करने का केंद्र बनती जा रही है। कई बार तो लगता है कि विधेयक पहले से तय होकर आते हैं और संसद सिर्फ उस पर मुहर लगाने की औपचारिकता निभाती है। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी ताकत होती है, पर जब संवाद घटता है, तो लोकतंत्र सिर्फ औपचारिक शब्द बनकर रह जाता है।

लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ केवल सत्ता पक्ष नहीं होता, बल्कि विपक्ष भी उसका हिस्सा होता है। विपक्ष कोई विरोधी दल नहीं, बल्कि लोकतंत्र का दूसरा फेफड़ा है। जब एक पक्ष बोलता है और दूसरा सुनता है, तभी यह प्रणाली सांस लेती है, मगर अब वह सांस घुटने लगी है। संसद में विपक्ष के बोलने के समय को सीमित किया जाना, असहमति को विघ्न मान लेना और सवाल पूछने वालों को 'अव्यवस्थित' करार देना, यह लोकतंत्र के चरित्र में आई सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। सत्ता को हमेशा सवालों की जरूरत होती है, क्योंकि सवाल ही उसे जमीन पर रखता है, लेकिन जब सवाल पूछने वाले कम हो जाएं या उनकी आवाज दबा दी जाए तो सत्ता जवाबदेह नहीं रहकर आत्मसंतुष्ट हो जाती है।

स्वतंत्रता के आरंभिक दो दशकों में संसद साल में औसतन एक सौ बीस से अधिक दिन चलती थी। अब वह संख्या आधी रह गई है। शीतकालीन सत्र का पंद्रह दिनों तक सीमित रहना उसी गिरावट का हिस्सा है। यह सिर्फ समय की कमी नहीं, अपितु लोकतांत्रिक संस्कृति के सिकुड़ने की कहानी है। संसद को अब जनता के सवालों से ज्यादा अपने कार्यक्रमों की चिंता है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट या शिक्षा पर चर्चा पीछे खिसक गई है। संसद वह जगह थी जहां जनता बोलती थी, अब वह जगह बन गई है जहां सरकार बोलती है और बाकी सिर्फ सुनते हैं।

सवाल पूछना लोकतंत्र का अपराध नहीं, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर सांसद जब अपनी सीट से खड़ा होकर कोई प्रश्न पूछता है, तो वह अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से बोलता है। जब उसे बोलने से रोका जाता है, तो यह एक तरह से उस जनता को चुप कराने जैसा है जिसने अपने वोट से उसे संसद तक पहुंचाया। यही कारण है कि संसद में कम होते सवाल, कम होते सत्र और बढ़ता मौन एक गहरी चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र की ताकत बहस में होती है और जब बहस सिमटने लगे तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र की सेहत गिर रही है। अब संसद का मौन डराने लगा है। पहले संसद में शोर था। गुस्सा भी था। बहसें भी थीं और कभी-कभी अव्यवस्था भी देखने को मिलती थी, लेकिन उस शोर में जीवंतता की अनुभूति थी। आज बहुत कुछ सुव्यवस्थित है, शांत है, तय है। शायद यही शांति लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है, क्योंकि जो संसद बोलना बंद कर देती है, वह जनता से सुनना भी बंद कर देती है। पंद्रह दिन का सत्र किसी राजनीतिक गणना का नतीजा हो सकता है, पर यह जनता के प्रतिनिधित्व के आत्मा पर प्रहार है। इतने कम समय में न कोई गहरी चर्चा हो सकती है, न किसी कानून के दूरगामी प्रभावों पर विचार। यह लोकतंत्र का 'संक्षिप्त संस्करण' है कि यह तेज तो है पर आत्महीन भी है।

लोकतंत्र को चलाने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, संवाद भी चाहिए। संसद को सिर्फ विधेयक नहीं, प्रश्न भी चाहिए। जो शासन संवाद से डरता है, वह अंततः जनता से दूर हो जाता है। संसद को अब समय की नहीं, गंभीरता की जरूरत है। यह वह जगह नहीं होनी चाहिए जहां सरकार केवल अपनी बात कहे, बल्कि वह मंच होना चाहिए जहां देश की हर आवाज, चाहे वह सत्ता की हो या विपक्ष की, उसे बराबरी और गंभीरता से सुना जाए। लोकतंत्र की सबसे सुंदर बात यही है कि वह बहस से चलता है, सहमति से नहीं। अगर संसद में अब सिर्फ सहमति बची है और असहमति को जगह नहीं दी जा रही तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र अब अपने मूल अर्थ से कहीं न कहीं दूर जा रहा है। लोकतंत्र का अस्तित्व संसद के शोर में है, उसकी चुप्पी में नहीं। संसद को चलाना ही पर्याप्त नहीं, उसे बोलना और सुनना भी चाहिए।

अभियान

त्रिवेणी की पुकार: प्रयागराज में माघ मास का महाआख्यान

प्रयागराज की पवित्र धरती हर वर्ष माघ मास आते ही एक ऐसी अदृश्य पुकार से भर जाती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसकी आत्मा गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम से किसी अदृश्य सूत्र में बंधी हो। सर्द जनवरी की सुबहों में जब धुंध गंगा किनारे तैरती हुई घूमने लगती है, तब लगता है जैसे आस्था स्वयं हवा बनकर पूरे शहर में फैल गई हो। इस बार का माघ मेला भी उसी चिरंतन परंपरा का हिस्सा है, परंतु इसके भीतर कुछ ऐसा है, जो इसे केवल एक धार्मिक अवसार नहीं रहने देता, बल्कि भारतीय चेतना का जीवित इतिहास बना देता है।

कहते हैं, संगम पर डाली गई एक छोटी-सी आस्था की डुबकी भी मनुष्य के भीतर वह प्रकाश जगा देती है, जिसे वह जीवनभर खोजता रहता है। शायद यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने वर्षा के रुकने भर की देर की और पूरा प्रयागराज माघ मेला बनाने में जुट गया। शहर की सड़कों पर, घाटों के किनारे, पुलों के नीचे-ऊपर, आकाश में उड़ते ड्रोन की निगाहों में और गंगा के किनारे उगते हर तम्बू में माघ महीने की तैयारी एक जीवंत उत्सव जैसी दिखने लगी।

लाखों नहीं, करोड़ों कदम इस बार संगम तट को छूने वाले हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक हर दिन अनगिनत यात्राएँ पूरी होंगी। दूर-दराज के गाँवों से, पर्वतों से, समंदर किनारे बसे नगरों से, विदेशी आसमानों की उड़ानों से—सब दिशा की भीड़ प्रयागराज की ओर बढ़ रही है। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा और अपनी आध्यात्मिक जड़ों से मिलने का क्षण है।

महाकुंभ 2025 की विराट स्मृतियाँ अभी भी हवा में तैर रही हैं। उस अद्भुत आयोजन में जितने लोग आए, वह संख्या किसी भी देश की आधी जनसंख्या से अधिक थी। उसी स्मृति ने इस बार के माघ मेले को अभूतपूर्व बना दिया है। गंगा किनारा अब केवल एक नदी का तट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़े अस्थायी नगरों में बदलने वाला है। इस बार प्रशासन ने हर गलती, हर कमी और हर चुनौती को मानो पहले ही पढ़ लिया है। पूरे शहर में सैकड़ों किलोमीटर की रौशनी की श्रृंखलाएँ, जल पुलिस के नए दस्ता, एसडीआरएफ की नावें, रात-दिन निगरानी करते फुटेज, सुरक्षित बैरिकेड और अनगिनत अप्रोच मार्ग—सब मिलकर प्रयागराज को एक चलती-फिरती व्यवस्था में बदल रहे हैं।

माघ मेला केवल व्यवस्था का चमत्कार नहीं, यह मनुष्य के भीतर छिपे तप की पुकार भी है। हजारों कल्पवासी इस बार फिर संगम तट पर एक पूरा महीना बिताने आएँगे। वे मिट्टी पर चादर बिछाकर, ठंडी हवा में सुबह-सुबह स्नान करके, धूप और अन्न पर नियंत्रण रखते हुए एक ऐसा जीवन जीते हैं, जो आधुनिक समय की किसी भी संस्कृति में दुर्लभ है। इस बार उनके तम्बुओं के लिए नई ऊर्जा-सक्षम लाइटें, साफ पानी, सुरक्षित चूल्हे, बायो-टॉयलेट और हर समय उपलब्ध चिकित्सा दल नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन के प्रयासों के बाद भी उनके चेहरे पर वही शांत सादगी रहती है, जिसे देखकर लगता है कि वास्तविक तप तो मन का होता है, व्यवस्था केवल उसका आधार।

भीड़ लाखों में हो, पर संगम का दृश्य फिर भी किसी आध्यात्मिक चित्र जैसा लगता है। घाटों पर लगातार बजते मंत्र, दूर कहीं गूँजती घंटियों की ध्वनि, जल की सतह पर तैरती दीपक की लौ और पाँवों से उठती हुई रेत की धूल—ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहाँ समय ठहर जाता है। लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं और गंगा किनारे बैठकर अपने भीतर झाँकने लगते हैं। वह क्षण, वह अनुभव, वह डुबकी—किसी पाठशाला में नहीं सिखाई जा सकती।

स्वच्छता इस बार का मूल मंत्र है। चोबीस घंटे सफाई कर्मी, GPS से चलते कचरा वाहन, नदी किनारे बायोडिग्रेडेबल डिब्बे और प्लास्टिक मुक्त अभियान पूरे क्षेत्र को एक अनुशासित, स्वच्छ और सुरक्षित आयोजन में बदल रहे हैं। हर ओर यह एहसास है कि आध्यात्मिकता तभी चमकती है जब उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ और संतुलित हो।

साधु-संतों की अखाड़ा परंपरा इस बार और विस्तृत रूप में दिखाई देगी। उनके शिविरों में बैठकर दिये जाने वाले प्रवचन, मंत्रोच्चारण, योग-समाधि की अनुभूतियाँ और अनगिनत श्रद्धालुओं का आना-जाना—यह सब मिलकर माघ मेले को वह पहचान देते हैं, जिसके कारण दुनिया इस आयोजन को भारत की आत्मा कहती है।

जब शाम ढलती है और गंगा किनारे गंगा आरती की लहरें उठती हैं, तब वह दृश्य किसी स्वप्न की तरह फैल जाता है। दीपकों की पंक्तियाँ पानी पर तैरती हुई आगे बढ़ती हैं और पूरा संगम क्षेत्र एक साथ झिलमिलाने लगता है। हवा में कपूर और धूप की सुगंध घुल जाती है। सैकड़ों, हज़ारों आवाजें एक साथ "हर हर गंगे" का मंत्र गूँजाती हैं और उस क्षण मनुष्य चाहे किसी भी देश, भाषा या संस्कृति से आया हो, वह स्वयं को इस दिव्यता का हिस्सा महसूस करने लगता है।

प्रयागराज का माघ मेला इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहाँ आस्था प्रशासन से मिलती है, परंपरा आधुनिकता से, साधु नगरवासियों से और विदेशी भारतीय संस्कृति से। यह आयोजन हर बार लौटता है, पर हर बार अपने भीतर कुछ नया लिए हुआ। इस बार भी वही होगा—वह अनंत भावना, वह अपार भीड़, वह श्रद्धा की धारा और वह पवित्र स्पर्श, जो मनुष्य के जीवन में कभी-कभी ही आता है। संगम की यह पुकार केवल लोगों को एक स्थान पर नहीं बुलाती, वह मन के भीतर सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। और यही माघ मेले की वह महानता है, जो इसे बाकी सभी आयोजनों से अलग करती है—यह केवल आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में पारसी धर्मगुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- राष्ट्र निर्माण में पारसियों का महामूल्यवान योगदान रहा है
- मैडम भीकाजी कामा, होमी भाभा, टाटा, वाडिया, गोदरेज परिवारों, फील्ड मार्शल माणेक शॉ आदि पारसियों का बड़ा योगदान रहा है
- दानवीरता का दूसरा नाम पारसी हैं, पारसियों ने भगवद् गीता का 'स्वधर्म' का संदेश आत्मसात किया है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में सोमवार को अहमदाबाद में पारसी धर्मगुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से पारसी धर्मगुरुओं को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म में निष्ठापूर्वक जीना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। पारसी समाज के पूर्वजों ने भारत में आकर गीता के 'स्वधर्म' के संदेश को जिया और कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। पारसियों ने भगवद् गीता का स्वधर्म का संदेश आत्मसात किया है। अपने धर्म की रक्षा के लिए 1300 वर्ष पहले वे ईरान से स्थानांतरण कर गुजरात आए और दूध मे चीनी की तरह घुल गए। राष्ट्र निर्माण में पारसियों का महामूल्यवान योगदान रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को सदियों से जतन करके रखा गया है, उसी तरह पवित्र आतश की रक्षा से धर्म का अस्तित्व बनाए रखने की गाथा का युगों तक जतन करने के लिए नवसारी में टाइम कैप्सूल रखकर इतिहास को अमर रखने का कार्य पारसी समुदाय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को यह टाइम कैप्सूल चरितार्थ करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की जो विभावना दी है, उसे पारसी समुदाय ने साकार किया है। साथ ही; उन्होंने पारसी समाज के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई पीएम जियो पारसी योजना का भी उल्लेख किया।

पारसी समाज गुजरात के सामाजिक जीवन में समरसता से घुल गया होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ-जहाँ यह समुदाय बसा, वहाँ दानवीरता-परोपकारिता का बीजारोपण हुआ है। उनके पूर्वजों ने हमेशा समाज को कुछ न कुछ दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि दानवीरता-परोपकारिता का दूसरा नाम पारसी हैं। अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट (एकेबेटी) पारसी समाज की दानवीरता की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि यह ट्रस्ट हेल्थकेयर, एजुकेशन तथा समाज कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में वंचित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। एचआईवी पीड़ित लोगों के लिए भी यह ट्रस्ट कल्याण के अनेक कार्य करता है। ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी पारसी समुदाय ने अपने संस्कारों, मूल्यों तथा सूझ-बूझ को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम काल से लेकर आज तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना देने वाले मैडम भीकाजी कामा, होमी भाभा, टाटा, वाडिया, गोदरेज परिवारों, फील्ड मार्शल सैम माणेक शॉ, फरदुनजी मर्जबान, नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी, फली नरीमान सहित पारसी अग्रणियों को इस अवसर पर याद किया।

पारसी समुदाय के प्रमुख धार्मिक अग्रणी दस्तूरजी श्री खुर्शीद दस्तूर ने अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट के कामकाज की प्रसंसा करते हुए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने पारसी सहित सभी समाजों को साथ लेकर सबके विकास के लिए निरंतर प्रयारसत रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अरीज खंभाता बेनेवोलेंट ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री पीरूज खंभाता ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास विद विरासत' का मंत्र दिया है। पारसी प्रिस्ट्स का सम्मान इस मंत्र को साकार करता है। विकास में अग्रसर रहने वाला गुजरात मुख्यमत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनशैली सहित हर मामले में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने जोड़ा कि विकसित भारत के निर्माण में पारसी समाज अपना सक्रिय योगदान देने को तत्पर है।

उन्होंने इस अवसर पर ट्रस्ट के कामकाज की जानकारी देकर आगामी समय में पारसी समाज में धार्मिक शिक्षा में आगे बढ़ रहे युवाओं के लिए शुरू की जाने वाली छात्रवृत्ति की घोषणा की।

यहाँ उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत पारसी समाज की नई पीढ़ी को उनकी परंपरा तथा संस्कृति के प्रति जागृत करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा नाटक, म्यूजिक एवं कॉमेजी जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में देशभर से पारसी समाज के लोग उपस्थित रहने वाले हैं।

इस अवसर पर प्रमुख दस्तूरजी श्री टेमटन मिर्जा, प्रमुख दस्तूरजी श्री साइरस दस्तूरजी, एकेबेटी की ट्रस्टी श्रीमती परसीस अरीज खंभाता, श्रीमती बिनाइसा पीरूज खंभाता, पारसी समाज के अग्रणी, सामाजिक संस्थाओं के अग्रणी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

नवंबर माह में ऑपरेशन अमानत के तहत RPF द्वारा यात्रियों के 12 लाख रुपये से अधिक की कीमत के छूटे सामान को लौटाया गया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल का रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए, वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने विभिन्न अभियानों के तहत नवम्बर ,2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।

मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने "ऑपरेशन अमानत" के तहत, यात्रियों के 12 लाख रुपये से अधिक की कीमत के यात्रिओं के कुल 83 छूटे हुए सामान को सफलतापूर्वक ढूंढकर उन्हें लौटा दिया।

वडोदरा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के रेलकर्मिओं द्वारा "आपरेशन दूसरा" के तहत बिना इजाज़त के फेरी लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ़ बल के जवानों द्वारा रेगुलर ड्राइव जारी है। नवंबर महीने में चलाये गए इस अभियान में कुल 1184 बिना इजाज़त फेरी लगाने वालों को गिरफ्तार किया गया और रेल अधिनियम 1989 की धारा के तहत उनका सामान ज़ब्त किया गया। इसके अलावा, उन पर एक्सेस फ़ेयर टिकट (EFT) लगाकर पेनल्टी लगाई गई। उनसे एक्सेस फ़ेयर टिकट (EFT) राशि के तौर पर कुल 1,19,440 रुपये इकट्ठा किए गए।

रेलवे सुरक्षा बल के इन सतत प्रयासों ने न केवल रेलवे परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी सशक्त बनाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 187वीं बैठक आयोजित होगी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी बैठक में सहभागी होंगे

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 187वीं बैठक 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 10.15 बजे गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल-1 स्थित नर्मदा हॉल में आयोजित होगी।

केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों में बैंकों के परफॉर्मेंस की समीक्षा एवं सुझावों के लिए समय-समय पर यह बैठक आयोजित की जाती है।

मंगलवार को आयोजित होने वाली एसएलबीसी की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कार्यपालक निदेशक श्रीमती सोनाली सेनगुप्ता तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधक एवं अधिकारी सहभागी होंगे।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले 3 अग्रणी जिला प्रबंधकों का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से ट्रॉफी तथा प्रमाणपत्र से सम्मान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त; एसएलबीसी द्वारा जुलाई-सितंबर-2025 तिमाही में विभिन्न योजनागत क्षेत्रों में बैंकों में हुए कामकाज की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति तथा सर्वग्राही समीक्षा भी की जाएगी।

4 दिसंबर की अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेगी

दक्षिण रेलवे के चेन्नई एग्मोर (MS) स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के दूसरे चरण के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 7, 8 एवं 9 पर किए जा रहे कार्यों के कारण लाइन ब्लॉक/पावर ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

4 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया रेनिगुंटा-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-मेलपक्कम-काटपाडी-वेलूर केंट-विल्लुपुरम के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन अरक्कोणम, पेरम्बूर, चेन्नई एग्मोर, ताम्बरम और चेंगलपट्टू स्टेशनों पर नहीं जाएगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान इस ट्रेन को तिरुत्तणि स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। ट्रेनों के ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

वैश्विक बाजारों में उमंग की लहर, एशिया से लेकर अमेरिका तक निवेशकों का बढ़ा भरोसा

सप्ताह के पहले ही दिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आने वाले उत्साहजनक संकेतों ने वैश्विक निवेश माहौल को बेहद सकारात्मक बना दिया। वॉल स्ट्रीट की मजबूत क्लोज़िंग, यूरोपीय सूचकांकों में बनी तेजी और एशिया के ज्यादातर बाजारों में हरे निशान की चमक ने मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा भर दी है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती स्थिरता, कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे और भू-राजनीतिक तनावों में हल्की नरमी जैसे कारकों ने मिलकर बाजारों को मजबूती दी है।

अमेरिकी बाजारों का बीते सत्र का प्रदर्शन दुनिया भर के ट्रेडरों के लिए एक बड़ा मनोबल साबित हुआ। वॉल स्ट्रीट में ऐसा उत्साह दिखा मानो निवेशक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद से भरे हों। एस एंड पी 500 ने लगभग आधा प्रतिशत चढ़कर 6,849.09 अंक का स्तर छू लिया। प्रौद्योगिकी शेयरों के मजबूत प्रदर्शन ने नैस्डैक को भी ऊपर की ओर धकेला और यह 151 अंक की बढ़त के साथ 23,365.69 अंक पर बंद हुआ। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स सोमवार की सुबह 0.41% नीचे फिसलकर 47,520.08 अंक पर दिखाई दिया, मगर इसके बावजूद अमेरिकी बाजारों की धारणा समग्र रूप से सकारात्मक बनी रही।

यूरोप की आर्थिक धड़कनों में भी मजबूती का अहसास साफ झलका। लंदन के एफटीएसई में हल्की लेकिन भरोसेमंद तेज़ी देखी गई और सूचकांक 9,720.51 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह फ्रांस का सीएसी 8,122.71 अंक और जर्मनी का डीएएक्स 23,836.79 अंक पर बंद हुआ। यह संकेत था कि यूरोपीय निवेशकों को भी अगले कुछ महीनों में बाजार की दिशा को लेकर बढ़ता विश्वास महसूस हो रहा है। महँगाई नियंत्रण में आने की उम्मीदें, ब्याज दरों में स्थिरता और कुछ क्षेत्रों में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों ने यूरोप में सकारात्मकता को बल दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई इस मजबूती का असर एशियाई बाजारों पर भी साफतौर पर देखा गया। एशिया के नौ प्रमुख सूचकांकों में से सात आज हरे निशान में दिखे। यह ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण है जब दुनिया भर में आर्थिक व राजनीतिक अनिश्चितताएँ बराबर बनी हुई हैं। हालांकि जापान का निक्केई 1.89% की तेज गिरावट के साथ 49,302 अंक पर आ गया। जापानी बाजारों में यह कमजोरी मुख्यतः विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव और कुछ तकनीकी शेयरों में बिकवाली के दबाव की वजह से देखी गई। ताइवान वेटेड भी 0.67% फिसलकर 27,441.24 अंक पर पहुंचा। बाकी एशियाई बाजारों में रौनक साफ दिखाई दी। भारत का गिफ्ट निफ्टी 0.34% की तेजी के साथ 26,476 अंक पर पहुंच गया, जिससे घरेलू बाजारों में खुलने से पहले ही सकारात्मक माहौल बनने लगा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.16% ऊपर चढ़ गया। थाईलैंड का सेट कंपोजिट लगभग एक फीसदी उछलकर 1,268.86 अंक पर पहुंच गया। हांगकांग के हैंग सेंग ने भी 0.93% की बढ़त के साथ 26,099 अंक का स्तर छू लिया। चीन का शंघाई कंपोजिट, इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट और कोरिया का कोस्पी भी हल्की लेकिन स्थिर बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे।

पूरी दुनिया में शेयर बाजारों की यह चमक न सिर्फ निवेशकों की उम्मीदों को बढ़ाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन समय का सामना करते हुए अब धीरे-धीरे संभलने लगी है। कंपनियों की बढ़ती कमाई, टेक सेक्टर का मजबूत प्रदर्शन और प्रमुख देशों में ब्याज दरों की स्थिरता निवेश माहौल को और भी उजला बना रही है। यदि यह रुझान बना रहा, तो आने वाले हफ्तों में बाजारों की चाल और भी उत्साहजनक हो सकती है।

मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर गुजरात का विलय, 15,000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ कंपनी की ताकत बढ़ी

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) के साथ विलय की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंजूरी मिलने के बाद यह विलय आज से प्रभावी हो गया। कंपनी ने विलय की आधिकारिक सूचना शेयर बाजारों को भेजते हुए बताया कि एसएमजी का अलग अस्तित्व अब समाप्त हो गया है और उसकी सभी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ और संचालन अब पूरी तरह एमएसआईएल में समाहित हो चुके हैं।

मारुति सुजुकी के अनुसार इस विलय के बाद उनकी अधिकृत शेयर पूंजी में 15,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो कंपनी की भविष्य की विस्तार योजनाओं और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम कंपनी के संचालन को अधिक कुशल और संगठित बनाने की दिशा में बड़ा रणनीतिक फैसला है।

शेयर बाजार की प्रतिक्रिया भी संतुलित रही। बीएसई पर मारुति सुजुकी के शेयर 0.15% की हल्की बढ़त के साथ 15,917.25 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जबकि एनएसई पर इसका मूल्य 15,914.00 रुपये दर्ज किया गया। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस विलय से मारुति सुजुकी न केवल उत्पादन और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में नई परियोजनाओं और उत्पाद विस्तार की क्षमता भी मजबूत होगी।

विलय के बाद कंपनी ने अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर जोर दिया है, जिसमें भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और नई तकनीकी मॉडलों के विकास के साथ-साथ विनिर्माण केंद्रों का विस्तार शामिल है। यह कदम मारुति सुजुकी के लिए वित्तीय और प्रबंधन दृष्टि से एक मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि विलय के कारण संचालन में कोई व्यवधान नहीं होगा और कर्मचारियों, सप्लायर्स तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इस विलय से उद्योग जगत में मारुति सुजुकी की स्थिति और भी मजबूती से स्थापित होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम देश में वाहन उद्योग की प्रतिस्पर्धा और वैश्विक निवेश आकर्षण को भी बढ़ावा देगा।

विदेशी आक्रांताओं जैसा व्यवहार भारत में अस्वीकार्य: जगद्गुरु रामभद्राचार्य का कल्कि महोत्सव में संदेश

संभल। संभल के एंचौड़ा कम्बोह स्थित कल्कि धाम में शुरू हुए सात दिवसीय श्री कल्कि कथा महोत्सव के पहले दिन पद्मविभूषण जगद्गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं और मीडिया के सामने भारत की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाव के महत्व पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत, संतों, कवियों और महापुरुषों की भूमि है और यहां किसी को विदेशी आक्रांताओं जैसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं है।

स्वामी रामभद्राचार्य ने स्पष्ट किया कि "भारत माता का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। यहां रहना है तो तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास जैसी मार्गदर्शक परंपराओं को अपनाना होगा, न कि अकबर या बाबर जैसी प्रवृत्तियों को।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक को 'वंदे मातरम' का सम्मान करना चाहिए और गाय को माता के रूप में पूजना चाहिए। उनके अनुसार, भारत माता का अपमान करने वाले बयानों और कृत्यों को इस देश में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पत्नी शब्द और उसकी परंपरागत अवधारणा पर आए विवादित बयान के संबंध में स्वामी रामभद्राचार्य ने स्पष्ट किया कि उन्होंने शास्त्रसम्मत दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा, "भारत में पत्नी शब्द की अवधारणा ही मान्य है। पत्नी पति को पतन से बचाने वाली होती है। यदि अंग्रेजी शब्द 'वाइफ' की कोई शास्त्रीय कसौटी पर व्याख्या सिद्ध होती है, तो मैं उसे त्रिदंड गंगा में अर्पित कर दूंगा।"

कल्कि महोत्सव में पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए एकत्र हुए। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम को विशेष कथा, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित लोग रामभद्राचार्य के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े संदेशों को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से उत्साहित दिखे।

सारण में कुख्यात अपराधी शिकारी राय की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी, जिले में सुरक्षा को लेकर बढ़ी उम्मीदें

पटना। सारण जिले में सोमवार सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। पुलिस ने नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय को गिरफ्तार किया, जो आधा दर्जन से अधिक संगीन मामलों में वांछित था। यह मुठभेड़ तब हुई जब आरोपी के खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी टीम ने छापेमारी की। मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ। इस गिरफ्तारी के बाद जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में उम्मीद जगी है।

सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि 30 नवंबर को छोटी तेलपा क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की त्वरित जांच के लिए एएसपी सदर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिले कि आरोपी शिकारी राय अख्तियारपुर नहर के पास छिपा हुआ है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया।

पूछताछ में शिकारी राय ने दरियापुर बिसही के निवासी भीषम राय उर्फ आजाद सिंह की हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि यह हत्या व्यक्तिगत रंजिश के चलते की गई थी। इसके अलावा आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को बिशनपुर ढाला के पास बगीचे में छिपा रखा था। जब पुलिस टीम हथियार बरामद करने के लिए मौके पर पहुंची, तो शिकारी राय ने टीम पर फायरिंग की और भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने के बाद मौके पर ही पकड़ लिया गया। घायल आरोपी और घायल पुलिस अधिकारी सुमन कुमार का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है।

पुलिस ने आरोपी के पास से दो पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस, दो खोखे, तीन मैगजीन और वारदात में पहना गया कपड़ा बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों के खिलाफ पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अब स्पीडी ट्रायल के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित टीमों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं।

स्थानीय लोग इस गिरफ्तारी से राहत महसूस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से जिले में अन्य अपराधियों के मनोबल को भी कमजोर किया जा सकेगा। अब जिले में आम लोगों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति भरोसा बढ़ा है।

शिकार राय की गिरफ्तारी सारण पुलिस की तत्परता और उत्कृष्ट समन्वय का परिणाम मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जिले में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। इस कार्रवाई ने सारण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा फिर से मजबूत किया है।

बाड़मेर में मिले रेयर अर्थ मिनरल्स, भारत बना सकता है हाई-टेक इंडस्ट्री का नया केंद्र

बाड़मेर, राजस्थान। दुनिया में जब भी रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है चीन का। लंबे समय से चीन ने इस क्षेत्र में अपनी मोनोपॉली कायम कर रखी है, जिससे अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी उसके सामने सीधे चुनौती देने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन अब चीन की इस प्रभुत्व वाली स्थिति को चुनौती देने वाला नया केंद्र उभरा है राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा का सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यहां नियोबियम समेत कई महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्व अत्यधिक घनत्व में पाए गए हैं। विशेषज्ञ इसे चीन के दशकों पुराने प्रभुत्व के लिए पहली वास्तविक चुनौती मान रहे हैं।

रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ खनिज नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी दुनिया की आधारशिला हैं। इनकी जरूरत इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, एयरोस्पेस, मिसाइल सिस्टम, रॉकेट टेक्नोलॉजी, लेजर तकनीक, सुपरकंडक्टर और परमाणु ऊर्जा जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में होती है। चीन ने वर्षों तक इन खनिजों का इस्तेमाल सामरिक और आर्थिक दबाव बनाने के लिए किया। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देश व्यापार युद्ध और वैश्विक रणनीतियों में चीन के प्रति सतर्क रहते हैं।

सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में बाड़मेर के कमठाई, दांता, थापन, भाटीखेड़ा, राखी फूलन और लंगेरा की पहाड़ियों में मिले खनिजों का आर्थिक मूल्य 900 अरब रुपये से अधिक आंका गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यहां लगभग 6,000 मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता मौजूद है। इस खोज से भारत न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि वैश्विक रेयर अर्थ मिनरल्स मार्केट में नई प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में भी उभर सकता है।

भू वैज्ञानिकों की मानें तो भाटीखेड़ा ब्लॉक का ऑक्शन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अगले 25 सालों तक यह क्षेत्र भारत की तकनीकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इस क्षेत्र में 15 प्रकार के महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्व पाए गए हैं, जिनमें गैलेनियम, रूबीडियम, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, टीलूरियम और लैंथोनाइड समूह के अन्य तत्व शामिल हैं। इन तत्वों का उपयोग एरोस्पेस प्लग मैग्नेट, हाइब्रिड कार, कैंसर मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण जैसे उच्च मूल्य वाले उद्योगों में किया जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सिवाना में मिले इन खनिजों के कारण चीन की वैश्विक दबाव वाली रणनीति कमजोर हो सकती है। इससे वैश्विक टेक सप्लाई चेन सुरक्षित होगी और अमेरिका और यूरोप को चीन का मजबूत विकल्प मिलेगा। भारत हाई-टेक इंडस्ट्री का नया केंद्र बन सकता है, और वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

हालांकि, इस खोज के बावजूद सुरक्षा और संरक्षण की चुनौती बनी हुई है। पिछले वर्षों में इस ब्लॉक में खनिज निकालने की चर्चा तो होती रही, लेकिन धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में खनिज विभाग द्वारा जारी ग्रेनाइट खनन लीज का गलत इस्तेमाल कर अवैध खनन भी हो रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो यह बेशकीमती खजाना नुकसान में जा सकता है।

सिवाना की यह खोज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से नया युग ला सकती है। यदि सही दिशा में निवेश और संरक्षण सुनिश्चित किया गया, तो देश दुनिया में हाई-टेक इंडस्ट्री में चीन का विकल्प बनने के साथ-साथ आत्मनिर्भर और सामरिक रूप से मजबूत बन सकता है।

इंदौर में नया गीता भवन, प्रदेश के हर नगर में होगा आधुनिक गीता भवन का निर्माणः CM मोहन यादव ने किया ऐलान

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश के शासकीय क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया गीता भवन लोकार्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी इसी तरह के गीता भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर का नया गीता भवन परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम है और यह राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक अध्ययन और सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा।

नई गीता भवन परियोजना के तहत ऐतिहासिक गोपाल मंदिर परिसर को आधुनिक गीता भवन के रूप में विकसित किया गया है। इसमें स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 550 सीट का अत्याधुनिक सभागृह बनाया गया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रवचनों और शैक्षणिक आयोजनों के लिए समर्पित है। इसके अलावा, भवन में 50-सीटर रीडिंग हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रदर्शनी कक्ष भी विकसित किए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में अध्यात्म, योग, दर्शन, ध्यान, भारतीय संस्कृति, माइंडफुलनेस और जीवन-प्रबंधन विषयों से संबंधित 1200 से अधिक पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। इसके साथ ही ऑनलाइन कोर्स, ई-बुक्स और ऑडियो-वीडियो व्याख्यानों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता जीवन में मार्गदर्शन, आत्मबल और संघर्षों से निपटने की शक्ति देती है। प्रत्येक अध्याय में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, योग और कर्तव्य की भावना समाहित है। भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप के माध्यम से मानव को भय से मुक्त कर कर्तव्य के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गीता जयंती के अवसर पर अनेक रिकार्ड बनाए गए और प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार, ई-रिक्शा, ई-बाइक, लैपटॉप आदि प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने गीता भवन का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए युवा पीढ़ी को शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन देना बताया। उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र की गौरवशाली विरासत, कृष्ण भक्ति और गीता का संदेश प्रदेश की दिशा तय करता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राज्य संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित श्रीकृष्ण चरित मानस और अमृतस्य अवंतिका का विमोचन भी किया तथा इन पुस्तकों के लेखकों को सम्मानित किया।

गोपाल मंदिर परिसर में निर्माणित गीता भवन में विशेष प्रदर्शनी कक्ष भी विकसित किए गए हैं, जो धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ कला और संस्कृति को बढ़ावा देंगे। लाइब्रेरी और सभागृह के आंतरिक सज्जा में प्राकृतिक रंगों, आध्यात्मिक कलाकृतियों, इनडोर पौधों और सौम्य प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को शांत, प्रेरणादायी और एकाग्र वातावरण मिल सके।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर के लिए यह दिन गौरव का है और राज्य सरकार की यह पहल सांस्कृतिक विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम से पहले गोपाल मंदिर में पूजन-अर्चन किया और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।

प्रदेश में नए गीता भवन निर्माण से न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह युवाओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जीवन के हर चरण में निर्णय क्षमता विकसित करने में सहायक भी साबित होगा।

लव मैरिज करने वाली महिलाएं SIR के भंवर में फंसीं, दस्तावेजों की कमी और मायके का विरोध बना बाधा

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लव मैरिज करने वाली कई महिलाओं को अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिन महिलाओं ने अपने प्रेमियों के साथ घर छोड़कर शादी की, उन्हें अब पहचान संबंधी दस्तावेज और पारिवारिक सहयोग की कमी के कारण गणना फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है। कई मामलों में महिला के परिवार ने संपर्क तोड़ रखा है, जिससे उनका मायके से आवश्यक दस्तावेज हासिल करना मुश्किल हो गया है।

कानपुर के चमनगंज में एक मुस्लिम युवती का मामला सामने आया, जिसने परिवार के विरोध के बावजूद हमीरपुर के एक युवक से लव मैरिज कर ली। अब SIR प्रक्रिया में उसे अपने पिता की पहचान और पुराने वोटर लिस्ट से पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है, लेकिन परिवार से संपर्क न होने के कारण यह असंभव हो रहा है। इसी तरह, किदवई नगर का एक युवक नोएडा में काम करते हुए राजस्थान की लड़की से प्रेम विवाह कर कानपुर में बस गया। लड़की के परिवार ने शादी को स्वीकार नहीं किया, और अब वह गणना फॉर्म भरने के लिए पिता का नाम और दस्तावेज दिखाने में असमर्थ है।

राजस्थान के उदयपुर में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। राहुल और वंदना की लव मैरिज के बाद वंदना का परिवार उससे कट गया। गणना फॉर्म भरने के लिए उसने मायके से दस्तावेज मांगने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने देने से इनकार कर दिया। अंततः राहुल ने पत्नी और अपने फॉर्म भरकर प्रशासन को जमा कराया।

विशेषज्ञों और प्रशासन का कहना है कि प्रारंभिक चरण में मतदाता को दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। उदयपुर की जिला कलेक्टर मित मेहता ने स्पष्ट किया कि सभी मतदाता, चाहे पुरुष हों या महिला, अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर जमा कराएं। जरूरत पड़ने पर प्रशासन बाद में सहयोग करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रागिनी शर्मा ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन उन माता-पिता को समझाने की कोशिश करें जो सहयोग नहीं कर रहे। विवाहिता स्वयं भी दस्तावेज एकत्रित कर सकती हैं, और फिर भी यदि समस्या आए तो एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। बदायूं के एसडीएम मोहित कुमार ने कहा कि प्रेम विवाह जैसी परिस्थितियों में भी कोई बाधा नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर व्यक्ति का डेटा उपलब्ध है। मतदाता अपने परिवार की एपिक आइडी देखकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि आइडी नहीं मिल रही, तो गणना फॉर्म के तीसरे विकल्प का उपयोग कर चार दिसंबर के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।

इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि प्रेम विवाह के बाद महिलाएं नए जीवन की शुरुआत तो कर चुकी हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं और SIR जैसी महत्वपूर्ण मतदाता पहचान प्रक्रिया के चलते उन्हें अब दस्तावेज और पारिवारिक सहयोग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की मदद, कानूनी उपाय और ऑनलाइन संसाधनों का सही उपयोग करके इस समस्या का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए महिलाओं को सचेत और सक्रिय होना आवश्यक है।

फतेहपुर में बाइक ट्रांसफार्मर से टकराई, दो युवकों की मौत, एक गंभीर

फतेहपुर। जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। खजुहा कस्बे के पास तीन युवकों की मोटरसाइकिल अचानक सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर के पक्के चबूतरे से टकरा गई। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया।

घायल युवकों की पहचान अमित कुमार (22) निवासी बकालपुर, जनपद एटा; शिवम कनौजिया (24) निवासी अमौली, जनपद फतेहपुर; और पुनीत तिवारी (23) निवासी हरईया, जनपद हरदोई के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल से सभी को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी पहुंचाया। डॉक्टरों ने अमित और शिवम को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल पुनीत को प्राथमिक उपचार के बाद हैलट अस्पताल, कानपुर भेजा गया।

जानकारी के अनुसार, तीनों युवक हैलट अस्पताल में एक्स-रे तकनीशियन का प्रशिक्षण ले रहे थे। हादसे के दिन वे एक दोस्त की बहन की शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। तेज रफ्तार और बाइक पर नियंत्रण खो जाने के कारण वे ट्रांसफार्मर के चबूतरे से जा भिड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं और गंभीर रूप से घायल पुनीत का इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पुष्टि के लिए सड़क की स्थिति, बाइक की गति और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के लिए खतरनाक रहती है। प्रशासन ने इस घटना के बाद सड़क सुरक्षा के उपाय बढ़ाने और सड़क किनारे खतरनाक स्थानों पर चेतावनी संकेत लगाने की दिशा में कदम उठाने की योजना बनाई है। यह हादसा न केवल युवाओं के परिवार के लिए दुखद है, बल्कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है।

उत्तर प्रदेश में बारातों में बच्चों को हुई दुर्घटनाएं, हर्ष फायरिंग और अनियंत्रित हालात में दो अलग घटनाओं में बालक घायल और मृत

नोएडा और प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई दो अलग घटनाओं ने एक बार फिर बारातों में हर्ष फायरिंग और सुरक्षा की अनदेखी के खतरों को उजागर कर दिया है। नोएडा के ग्राम नगला चमरू में रविवार रात को एक बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग से 10 वर्षीय बालक कृष को गोली लगी, जबकि प्रतापगढ़ के चौबेपुर गांव में छह वर्षीय यश बारात में शामिल होने गया और रात में ही लापता हो गया, जिसका शव सोमवार सुबह घर के पास के खेत में मिला। नोएडा की घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) सुधीर कुमार ने बताया कि बारात में शामिल लोगों ने लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की। इस दौरान बालक कृष बारात को देख रहा था, तभी गोली उसके सिर में लग गई। उसे तुरंत उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर दो लोगों को हिरासत में लिया है और हथियार भी बरामद कर

पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया कि फायरिंग में इस्तेमाल लाइसेंसी हथियार एक रिटायर्ड फौजी के नाम से पंजीकृत था, और उसका बेटा बारात में इसे लेकर आया था। पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। वहीं, प्रतापगढ़ में छह वर्षीय यश के साथ हुई घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। चौबेपुर गांव निवासी बाबूलाल का पुत्र यश घर के बगल आई बारात में शामिल होने गया था, लेकिन आधी रात के बाद से लापता हो गया। ग्रामीणों ने सोमवार सुबह उसका शव पास के खेत में पाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रशांत राज ने बताया कि बालक के शव की पहचान हो चुकी है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। दोनों ही घटनाओं ने बारातों में सुरक्षा उपायों और हर्ष फायरिंग की खतरनाक प्रवृत्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी बारात में हथियार का प्रयोग खतरनाक परिणाम ला सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों से बचें और बच्चों को भी सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसों को रोका जा सके। इन घटनाओं के बाद प्रशासन और पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि जो भी व्यक्ति हर्ष फायरिंग या अवैध हथियार के प्रयोग में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग भी बच्चों की सुरक्षा और विवाह समारोहों में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

गुजरात में ऊना हाईवे पर 10 शेरों का झुंड, स्थानीय लोगों में रोमांच और हैरानी का माहौल

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने हर किसी को हैरानी और रोमांच, दोनों का अनुभव कराया। सौराष्ट्र क्षेत्र की पहचान माने जाने वाले एशियाई शेर अक्सर जंगलों और आसपास के गांवों में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार जो दृश्य नजर आया वह सामान्य नहीं, बल्कि बेहद अनोखा था। ऊना-गिर गढडा हाईवे पर अचानक आठ से दस शेरों का एक पूरा झुंड सड़क पर आराम से टहलता हुआ दिखाई दिया। इस झुंड में वयस्क शेरों के साथ छोटे शावक भी शामिल थे, जिससे यह पूरी तरह एक परिवार के रूप में नजर आया।

जैसे ही वाहन चालक शेरों के सामने आए, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दी और सुरक्षित दूरी बनाए रखी। करीब एक मिनट तक शेरों का यह परिवार बिना किसी डर या जल्दबाजी के हाईवे पर चलता रहा। कई यात्रियों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की कतार लग गई, लेकिन किसी ने भी शेरों को परेशान करने की कोशिश नहीं की।

स्थानीय लोग बताते हैं कि गिर क्षेत्र में शेरों का गांवों या हाईवे के पास दिखना कोई नई बात नहीं है। लेकिन आम तौर पर केवल एक-दो शेर दिखाई देते हैं। दस शेरों का एक साथ सड़क पर दिखाई देना बेहद दुर्लभ माना जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह दृश्य शेरों की बढ़ती संख्या और उनके संरक्षण में हो रही सफलता का परिणाम है। जंगल और आसपास के क्षेत्र में शेरों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के प्रयासों ने ही ऐसे अनोखे नजारों को संभव बनाया है।

इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि सौराष्ट्र में इंसान और शेर के बीच का रिश्ता कितना मजबूत और संतुलित है। यहाँ के लोग शेरों को केवल जंगल का राजा ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक धरोहर मानते हैं। ऊना हाईवे पर रात में दिखाई दिए शेर परिवार ने भले ही कुछ यात्रियों को डराया, लेकिन यह दृश्य प्रकृति के संतुलन और सुंदरता का जीवंत उदाहरण भी था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दृश्य वन्य जीवन और मानव जीवन के बीच तालमेल का प्रतीक हैं और यह संदेश देते हैं कि शेरों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास सफल हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने भी इस घटना पर ध्यान देते हुए कहा कि क्षेत्र में शेरों की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। वन विभाग ने आगाह किया कि लोग शेरों के करीब न जाएँ और उनका अनुभव केवल दूर से ही लें। इस दुर्लभ झुंड ने न सिर्फ लोगों के दिलों में रोमांच पैदा किया, बल्कि उन्हें प्रकृति के अद्भुत संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के महत्व का एहसास भी कराया।

पटना में बुलडोजर अभियान तेज, अवैध दुकानों और कब्जों पर कड़ी कार्रवाई जारी

पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही राजधानी पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नव-निर्वाचित विधायकों के विधानसभा शपथ ग्रहण के बीच, पटना नगर निगम (PNMC) की टीम बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतर चुकी है और अवैध निर्माणों व कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से सड़क किनारे बनी दुकानों और निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस अभियान के तहत अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, दुकानदारों के सामान जब्त किए जा रहे हैं और अतिक्रमण करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पटना के डीएम त्यागराजन एस.एम. ने दिसंबर महीने से शहर में एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस अभियान के लिए एक विस्तृत कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें कार्रवाई की पूरी रूपरेखा तय की गई है। डीएम और एसएसपी ने मिलकर नौ टीमों का गठन किया है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ अभियान चलाएँगी।

विशेष अभियान केवल पटना नगर निगम क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके दायरे में पटना के सभी छह अंचल—नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद और पटना सिटी शामिल हैं। इसके अलावा आसपास के शहरी निकाय जैसे नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत में भी यह अभियान चलेगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से शहर की सड़कें जाम-मुक्त होंगी और आम जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी। डीएम और नगर निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान दिसंबर भर चलेगा और इसे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान से न केवल सड़क जाम कम होंगे, बल्कि शहरी नियोजन और सुरक्षा में भी सुधार आएगा। वहीं, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान नागरिकों से सहयोग अपेक्षित है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इस व्यापक अभियान ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है, और यह संदेश दिया है कि अब पटना में कानून व्यवस्था और नागरिक सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है।